आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मिलों द्वारा अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि

514. श्री बलवंत सिन्हा :
सरदार बलजीत सिंह अरोड़ा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में चार पेपर अखबारी कागज की मिलों द्वारा कुछ ही महीनों में अखबारी कागज की कीमत में भारी वृद्धि की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है ;

(ग) क्या सरकार ने समाचार पत्रों पर पड़ने इस वित्तीय भार से उन्हें राहत दिलाने के लिये कोई ठोस उपाय किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी, 1988 की कीमत की तुलना में 52 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के अखबारी कागज की कीमतों में 28 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) अखबारी कागज की कीमतों पर केन्द्रीय सरकार का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और कीमतों में कटौती करना संभव नहीं हो पाया गया है ? तथापि छोटे और मझोले समाचार पत्रों को कठिनाईयों को देखते हुये, सरकार ने मौजूदा रियायतों के अलावा वर्ष 1989-90 का अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार चिकने अखबारी कागज के पन्ने छोटे अखबार पत्रों/पत्रिकाओं को चिकने अखबारी कागज पर सीमा शुल्क में शत प्रतिशत और मझोले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है । नेपा मिल से छोटे और मझोले समाचार पत्रों को अखबारी कागज देने की घोषणा की गई है । नेपा मिल देश में सबसे सस्ता अखबारी कागज देती है । प्रशासनिक और परिवहन खर्चा को कम करने के लिये 200 मीट्रिक टन तक के पात्र समाचार पत्रों को मिल से आवंटन के बजाय डाहाँ आवंटन किया जाता है । छोटे और मझोले समाचार पत्रों को भारतीय वित्त वित्त निगम से आयातित अखबारी कागज दिलवाये जाने को भी प्राथमिकता दी जायेगी । अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार सरकार ने सभी समाचार पत्रों को अखबारी की प्रयाप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाये हैं ।

Supply of Rice to Tribute under the Integrated Tribal Development Project

575. STR.I N.E. BALRAM : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to stats :

(.'0 whether Gevernment issue rice to certain predominantly tribal States at special food-grains subsidy scheme to be distributed among tribals under the Integrated Tribal Development Project ;

(b) if so, what is the issue price of rice under this scheme and the States to which rice is issued under this scheme ;

(c) whether the State agencies are allowed to add a certain amount to the issue price to defray transportation and distribution cost, if so, the details thereof ; and

(d) whether Government are aware of the fact that certain States are charging higher price of rice to be issued to tribals under Integra ted Tribal Development Projects, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD